भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

(21–22–23 सितम्बर, 2007)
स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार
पं0 दीनदयाल परिसर (भोपाल)

अध्यक्षीय भाषण

मित्रों,

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पधारे सभी सदस्यों का मैं राजाभोज की नगरी, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं **कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की राजनैतिक यात्रा में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक भूमिका रही है।** मध्य प्रदेश राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कर्मस्थली रही है। मध्य प्रदेश का संदर्भ हो तो स्व0 कुशाभाऊ ठाकरे को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने अनवरत् प्रवास और अथक परिश्रम से गांव–गांव तक संगठन का विशाल स्वरूप खड़ा किया। मध्यप्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वदा सबल और संघर्षशील रहा है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश की जनता ने कई बार हमको समर्थन देकर सत्ता में पहुंचाया है।

तीन माह पूर्व दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम सब मिले थे। इन तीन महीनों में राजनैतिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं और कई भावी परिवर्तनों के संकेत प्रकट हुये हैं। इन तीन महीनों में भारत की स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे हुये। देश में नये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला और केन्द्र में केवल भाजपा विरोध के नकारात्मक आधार पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के सहयोग से चल रही यूपीए सरकार अपने स्वाभाविक कारणों से पतन की ओर बढ़ती दिख रही है।

पिछले दिनों कांग्रेस और वामपंथी दलों के संबंध जिस प्रकार से तनावपूर्ण होते हुए दिखाई पड़े उससे यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ ही रहा है **कि लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है।** परन्तु इसके दो और निष्कर्ष भी बहुत स्पष्ट हैं। पहला तो यह कि **केवल नकारात्मक विरोध के आधार पर बनी हुई सरकारें कभी देश में सकारात्मक वातावरण का निर्माण नहीं कर सकती।** विगत तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर बढते आतंकवाद और बढ़ती महंगाई तक का सारा परिदृश्य इस बात का प्रमाण है। दूसरा यह कि यदि **गठबंधन राजनीति आज की राष्ट्रीय राजनीति की अपरिहार्यता है तो गठबंधन राजनीति के धर्म का अनुपालन करते हुए देश को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है।** वाजपेयी सरकार और सोनिया जी की छत्रछाया में चल रही मनमोहन सरकार के कार्यकाल इस अंतर के स्वयं प्रमाण हैं।

विगत तीन वर्षों में यूपीए सरकार के निराशाजनक कार्यकाल स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि यूपीए सरकार गठबंधन धर्म को समझने एवं उसका अनुपालन करने में

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

पूर्णतः अक्षम है जबकि यह आज की राष्ट्रीय राजनीति की अपरिहार्यता बन चुकी है। गठबंधन सरकारों को चलाने के लिए एक राजनैतिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है जो परिपक्वता एनडीए सरकार और भाजपा ने दिखाई थी और इस भ्रम को समाप्त कर दिया कि स्थायित्व सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। अटल जी ने एनडीए सरकार के कुशल संचालन के द्वारा भारतीय राजनीति में एक युगान्तर स्थापित किया। आज आवश्यकता है उसे और अधिक दृढ़ता एवं विस्तार प्रदान करने की।

स्पष्ट है कि **विषय विकास का हो अथवा स्थायित्व का, विषय आतंकवाद पर नियंत्रण रखने का हो अथवा महंगाई पर नियंत्रण रखने का, आज देश की जनता के सामने एकमेव विकल्प भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार ही हो सकती है। अतः हम एनडीए को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। ताकि हम एक साथ आगे बढ़ कर पुनः जनता का विश्वास हासिल कर सकें।**

आज हमारे सामने देश की बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियां अवसर प्रदान कर रही है कि हम पुनः भारत की राजनीति के केन्द्र में स्थापित हो सके। परन्तु यह तभी सम्भव होगा जब हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलने की क्षमता रखते है।

स्वतंत्रता के 60 वर्ष

देश ने हाल ही में स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई। आजादी के 60 साल बीत गए, एक नया भारत बनाने का स्वप्न लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों ने जो बलिदान किये थे, उनके स्वप्न कितने सार्थक हो सकें, यह भी विचार का विषय है। देश ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई। भाजपा इस वर्षगांठ के कार्यक्रम देश भर में कर रही है। लम्बे संघर्ष के बाद मिली आजादी का मूल्यांकन आज हमारे लिए आवश्यक है।

आज का भारत विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, विश्व का उभरता हुआ बौद्धिक केन्द्र है, विश्व की एक स्थापित सामरिक महाशक्ति है। ये तीनों ही कार्य एनडीए सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में प्रारंभ हुये थे। आज जब यूरोप की आर्सेलर और कोरस जैसी बड़ी–बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा किया जाता है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। क्योंकि ऐसा आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले तीन वर्षों में जितनी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है वह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। **भारत के आर्थिक परिदृश्य की दो अलग–अलग तस्वीरों का अंतर इतना बड़ा और विद्रूप है, यह एक राष्ट्रीय चिंतन का विषय होना चाहिए।** यह विषय केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि इसके राजनैतिक परिणाम भी होते हैं। विगत वर्षों में अनेक अच्छी सरकारें, जिन्होंने विकास के अनेक सराहनीय कार्य किये वे चुनावी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। विश्लेषकों ने उसका एक कारण आम गरीब, निर्धन, मजदूर और किसान की प्रतिक्रिया को भी माना।

भाजपा का वैचारिक अधिष्ठान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। विगत दो दशकों में पश्चिमी मॉडल पर जिस तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है, वह उतनी ही तेजी से पश्चिमी जीवन

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

मूल्य हमारे शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों और परिवार के स्वरूप पर भी आघात कर रहे है। अन्य राजनैतिक दल भले ही इसे गंभीरता से न लेते हों परन्तु भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में, मैं इसे एक गंभीर चुनौती मानता हूं।

स्वतंत्रता के 60 वर्ष की उपलब्धि और चुनौती को यदि एक वाक्य में कहना हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि **भारत के भविष्य की सबसे बड़ी आशा की किरण है हमारी बढ़ती आर्थिक समृद्धि और बढ़ती बौद्धिक सम्पदा। भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी निर्धनता और सामाजिक मूल्यों का क्षरण।**

इन 60 वर्षों में 54 वर्ष तक देश पर कांग्रेस और तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का नेतृत्व रहा। और 6 वर्ष तक भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार का शासन रहा। आज देश की जनता के सामने बिल्कुल साफ है कि वह तुलना करके देख ले कि एक तरफ है 60 साल का नेतृत्व और दूसरी तरफ है 6 साल का नेतृत्व। **60 साल बनाम 6 साल की यह तस्वीर भाजपा और शेष अन्य दलों की क्षमता और सामर्थ्य का अंतर बताने के लिए पर्याप्त है।**

विगत तीन माह

विगत तीन महीनों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। यह दोनों पद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं। इन पदों पर आसीन व्यक्तियों की गरिमा के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि इन पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया भी सर्वानुमति और गरिमा के साथ संपन्न हो। एनडीए सरकार के शासनकाल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर हमने सत्ताधारी दल के रूप में स्वयं सर्वानुमति की पहल की थी। परन्तु इस बार वर्तमान सत्ताधारी दल ने सर्वानुमति की बात तो छोड़िए इस विषय पर प्रमुख प्रतिपक्षी दलों से कोई प्रकारांतर से वार्ता भी नहीं की। **भाजपा का यह मानना है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर निर्वाचन यथासंभव सर्वमान्य और निर्विरोध रूप में होना चाहिए,** ऐसा ही विचार हमारे शीर्ष नेता आदरणीय अटल जी पहले ही व्यक्त कर चुके हैं।

इसी समय में पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें भाजपा–अकाली गठबंधन को शानदार सफलता मिली और सभी नगर निगमों पर हमारे गठबंधन का आधिपत्य हो गया। इस हेतु मैं पंजाब इकाई को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि पंजाब में हमारा संगठन और गठबंधन दोनों मजबूत होकर निरंतर आगे बढेंगे।

बिहार के अनेक इलाके गंभीर बाढ़ की चपेट में रहे। बिहार में भाजपा–जद–यू गठबंधन की सरकार है। हमारी गठबंधन सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये। **इस आपदा में हुई जान और माल की हानि के लिए हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।**

इन्हीं दिनों असम में हिन्दी भाषी कामगारों की आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई। इस परिस्थिति के आकलन के लिए श्री कलराज मिश्र के नेतृत्व में पार्टी ने एक

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जांच समिति भेजी थी। **ऐसे कार्य राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के कुत्सित प्रयास हैं। भाजपा उसकी निंदा करती है** और इस घटना में जान गंवाने वाले सभी व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

यूपीए सरकार की असफलता

आज केन्द्र सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम common minimum programme अब केवल सत्ता संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम या common minimum priority बन गया है। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आम आदमी और उसके प्रति संवेदना पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। निरंतर बढ़ती ब्याज दरें, निरन्तर बढ़ती महंगाई, निरन्तर बढ़ती कर की दरें ही इस सरकार की उपलब्धियां कही जा सकती है।

महंगाई और किसानों की आत्महत्या की सच्चाई तो आज जनता के सामने है ही, परन्तु आम आदमी के साथ के दावे पर बनी कांग्रेस की सरकार ने सर्वाधिक निराश युवाओं और महिलाओं को किया है। **महिला आरक्षण बिल का अभी तक कोई मसौदा भी तैयार नहीं किया गया है।** सुषमा जी की अध्यक्षता में पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो समिति पिछली कार्यकारिणी में बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट इस कार्यकारिणी में मुझे प्रदान की जायेगी और तब हम सब इस विषय की विस्तार से चर्चा करेंगे।

हमारी सरकार ने युवाओं के रोजगार के नये अवसर उत्पन्न किये थे परन्तु इस सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के नाम पर केवल पुरानी योजनाओं पर एक नया मुलम्मा चढ़ाने का काम ही किया है।

मुझे समझ नहीं आता है कि वही प्रधानमंत्री जो आतंकवादियों के प्रति इतने नरम रहना चाहते हैं कि वे जीरो टालरेंस की बात करते हैं। परन्तु **महंगाई की मार के नीचे कराह रहे आम आदमी और कर्ज के बोझ के तले दब कर आत्महत्या कर रहे किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की टालरेंस की सीमा क्या है, यह भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।**

आतंकवाद

केन्द्र में कांग्रेस और वामपंथी दलों के सहयोग से चल रही यूपीए सरकार ने आम आदमी से लेकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि तक सभी स्तरों पर निराश किया है। हाल ही में हैदराबाद में आतंकवादियों ने बम धमाके में अनेक लोगों की जान ली। हम सब इस आतंकवादी वारदात में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। परन्तु यह यूपीए के शासनकाल में कोई नई घटना नहीं है। इससे पूर्व बंगलौर, मुम्बई, औरंगाबाद, दिल्ली, काशी, अयोध्या और नागपुर इसके शिकार बन चुके हैं। ये सभी शहर भारत की किसी न किसी विशिष्ट पहचान के प्रतीक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसियों, विदेशी गुप्तचर एजेंसियों और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बावजूद ये घटनायें लगातार हो रही हैं।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की जनता को आज भय और आतंक के साये में जीना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार का आतंकवाद एवं आतंकवाद को समर्थन देने वाली शक्तियों के प्रति अत्यधिक नरम रवैया है। इसी कारण से आतंकवादी शक्तियों के हौसले आसमान छू रहे है।

एक अत्यधिक चिन्ता का विषय यह है कि भारत की आन्तरिक सुरक्षा केवल सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों एवं आतंकवाद से लड़ने की इच्छाशक्ति के अभाव से ही ग्रसित नहीं है, बल्कि अब तो आन्तरिक सुरक्षा संबंधी नीतियों को भी वोट बैंक के राजनैतिक नजरियें से देखा जाने लगा है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलकायदा ने अमेरिका के साथ–साथ भारत में भी बड़ी आतंकवादी कार्यवाहियां करने की चेतावनी दे रखी है। यदि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अन्दर की उथल–पुथल और अस्थिरता को इसके साथ मिलाकर देखें तो यह और भी आवश्यक लगने लगता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत इरादें और दूरदृष्टि दोनों की आवश्यकता है। **समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भारतीय सेना की नार्दन कमांड के प्रमुख ने रमजान के महीने के दौरान युद्ध विराम के किसी सरकारी प्रयास का विरोध करते हुए यह भी कहा था** कि कश्मीर में करीब 4 से 5 हजार आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए 52 कैंप चल रहे हैं। **इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना को जम्मू कश्मीर में मौजूदा संख्या से करीब दस गुना अधिक सैनिकों की आवश्यकता है।** इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि परिस्थितियों एवं सेना की तैनाती बढ़ाने की स्पष्ट मांग के ठीक विपरीत सरकार जम्मू काश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र से सेना की वापसी के निर्णय ले रही है। ऐसा कोई भी निर्णय अत्यंत घातक सिद्ध होगा।

देश के अनेक स्थानों पर नक्सली हिंसा लगातार उठान पर है। असम में लगातार हिन्दी भाषियों पर आतंकवादी हमले हो रहे है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को नियंत्रण करने तथा जनसामान्य में विश्वास उत्पन्न करने में सरकार पूरी तरह विफल दिखाई पड़ रही है।

आतंकवाद के आरोप में यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो तो हमारे प्रधानमंत्री को रात भर नींद नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी ही संवेदना इस सरकार को तब महसूस नहीं होती जब हमारे सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के हमले का शिकार होते हैं अथवा आतंकवादियों की गिरफ्त में तरह–तरह की यातनायें सह कर भी देश की सुरक्षा के रहस्य प्रकट नहीं करते। **सरकार का आतंकवाद के आरोपी और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने वाले सिपाहियों के प्रति यह विभेदकारी रवैया भर्त्सना के योग्य है।** भाजपा की ओर से मैं आतंकवाद के विरूद्ध लड़ रहे सुरक्षा बलों के सभी जवानों के प्रति अपनी संवेदना और संबल को व्यक्त करता हूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के ऐसे नाजुक हालात होने पर आतंकवाद को बल प्रदान करने वाली शक्तियों को एक साफ और दो टूक संदेश देने के बजाय सरकार साम्प्रदायिकता और तुष्टीकरण के राजनैतिक लाभ के गुणा भाग में व्यस्त है। **भाजपा राष्ट्र की आन्तरिक**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सुरक्षा के गंभीर विषय को क्षुद्र साम्प्रदायिकता एवं यूपीए के घटक तथा सहयोगी दलों के मध्य वोट बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति की बलिवेदी पर चढ़ने नहीं देगी। देश ने आतंकवाद की बहुत कीमत चुकायी है। प्रधानमंत्री महोदय कृपया तुष्टीकरण की राजनीतिक से उपर उठिये, आतंकवाद की शिकार हजारों मासूम जानों की तरफ देखिए और देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को तार–तार होने से बचाइयें।

एक राष्ट्रवादी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सरुक्षा के हितों पर कोई समझौता नहीं होने देगी हम सरकार की ऐसी हर नीति का विरोध करेंगे। **यदि आज भी सरकार आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध में कोई ईमानदार प्रयास करती है तो हम उसे भरपूर सहयोग देंगे।**

यूपीए सरकार पोटा को वापिस लेने को अपनी एक उपलब्धि बताती है। हमने सदैव से इसका विरोध किया। हमने वैकल्पिक कानून की मांग भी की। **आज भारत विश्व का एकमात्र बड़ा देश है जो अलकायदा तथा अन्य तमाम बड़े आतंकवादी संगठनों के निशाने के होने के बावजूद बगैर किसी आतंकवाद विरोधी कानून के आतंकवाद से लड़ रहा है। यह गैर बराबरी की लड़ाई है, सुरक्षा बलों का मनोबल इससे कम होता है। यदि भाजपा को पुनः केन्द्र में सत्ता का अवसर मिला तो वर्तमान सरकार की इस नीति को पलटकर हम आतंकवाद के विरूद्ध दृढ़ता से खड़े होंगे और एक प्रभावी आतंकवाद विरोधी कानून बनायेंगे।**

सच्चर कमेटी

वोट बैंक की राजनीति के अंधी दौड़ में वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई सच्चर समिति ने अनेक अविवेकपूर्ण सिफारिशें की हैं। परन्तु केन्द्र सरकार ने उन्हें यथावत लागू करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार द्वारा हाल में लिये गये एक निर्णय के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने समस्त राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह निर्देश दिये हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस चौकी पर मुस्लिम पुलिसकर्मी नियुक्त किये जायं तथा यथासंभव मुस्लिम अध्यापक और स्वास्थ्यकर्मी भी नियुक्त किये जायं। यूपीए सरकार साम्प्रदायिक राजनीति का एक ऐसा खौफनाक पिटारा खोलने जा रही है जोकि हमारे देश की एकता और अखंडता को तार–तार कर सकता है। इससे पूर्व सेना में मुस्लिमों की गणना और प्रधानमंत्री द्वारा देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार मानना जैसे अनेक कार्य इस सरकार द्वारा किये जा रहे हैं जो कि देश में साम्प्रदायिक विद्वेष का गहरा जहर घोल रहे हैं।

संसाधनों पर किसी सम्प्रदाय का पहला हक, सेना का साम्प्रदायिक विभेदीकरण, बैंक के कर्जों में किसी सम्प्रदाय को प्राथमिकता और अब पुलिस और सुरक्षा में साम्प्रदायिक नजरिया। क्या यह देश के पंथनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा के लिए हो रहा है? क्या यह भारत के वर्तमान संवैधानिक स्वरूप को सुदृढ़ करने का हेतु बन सकेगा? क्या इससे साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा अथवा वैमनस्य बढ़ेगा? मैं, **देश की जनता के सामने पार्टी की ओर से यह प्रश्न रखना चाहता हूं। देश की जनता इस पर विचार करे और सरकार को इसका समुचित प्रत्युत्तर दें।**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग की बात की है। ऐसे साम्प्रदायिक वातावरण में समान अवसर की बात युक्तिसंगत नहीं लगती। यदि सरकार ईमानदारी से समान अवसर आयोग का विचार कर सकती है तो समान नागरिक संहिता का विषय जिसके लिए न्यायालय द्वारा अनेकों बार आग्रह किया जा चुका है, सरकार इसके इतना विरूद्ध क्यों है?

विस्मृत होता ग्राम स्वराज

गांव, गरीब और किसान हमारे लिए एक नारा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था का यह मुख्य आधार है। भारत के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले हर नेता ने इस मर्म को समझा। चाहे वह महात्मा गांधी रहे हों, विनोबा भावे अथवा हमारे वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। **गांधी का ''ग्रामोदय'', विनोबा जी का ''सर्वोदय'' और दीनदयाल जी का ''अंत्योदय'' यह सब मूलतः ग्राम आधारित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सशक्तीकरण के स्वरूप थे।** महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य का उद्घोष भी किया था। आज महात्मा गांधी की विरासत के स्वयंभू उत्तराधिकारी देश की सत्ता का संचालन कर रहे हैं। परन्तु यह ऐसा स्वराज्य है जिसमें से ग्राम विलुप्त हो चुका है। हमारी कल्पना, हमारे मानस में उठने वाली विकास की योजनाओं और समस्त परिकल्पनाओं से मानो गांव गायब होता जा रहा हो। भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। हमारा स्पष्ट यह मानना है कि सरकार हो या संगठन गांव की इकाई को समाज के विकास का मुख्य आधार बनाना चाहिए। इसलिए **गांव, गरीब और किसान केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारी राजनैतिक सोच का अपरिहार्य अंग है।**

किसानों की उपेक्षा

तेजी से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर भारत में शहर के गरीब और गांव के किसानों को अपना समुचित अधिकार मिल सके, इस हेतु भाजपा पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसानों की यूपीए सरकार में निरंतर हो रही उपेक्षा। आर्थिक ऋण के दुष्चक्र में फंसकर आत्महत्या करते किसान, बीज और खाद की निरंतर बढ़ती कीमतें, समुचित समर्थन मूल्य का प्राप्त न होना और खाद्यान्न आयात के संदर्भ में सरकार की अनुचित ही नहीं बल्कि संदिग्ध नीति आदि ने मिल कर ऐसा वातावरण बनाया है कि केन्द्र की वर्तमान यूपीए सरकार किसानों के लिए एक दुःस्वप्न के समान हो गई है। किसानों की इसी समस्या को प्रभावी रूप से उठाने के लिए भाजपा ने विगत 20 अगस्त को दिल्ली में एक विशाल किसान रैली की और फिर संसद की ओर मार्च करते हुए आदरणीय आडवाणी जी और मेरे समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और हजारों किसानों ने गिरफ्तारी दी। **किसान रैली की सफलता ने हमारे उन आलोचकों के मुंह बंद कर दिये हैं जो भाजपा की जमीनी ताकत के लिए संशय व्यक्त करते थे।** किसान रैली की इस सफलता के लिए मैं भाजपा संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं, भाजपा किसान मोर्चा को बधाई देता हूं। किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा एक व्यापक आन्दोलन का विचार रखती है। इस कार्यकारिणी में हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

गेहूं आयात घोटाला

इस सरकार की गेहूं आयात की नीति न सिर्फ दिशाहीन है, न सिर्फ किसानों के लिए संवेदनहीन है बल्कि संदिग्ध दिखाई पड़ती है। विगत तीन महीनों में सरकार ने पहले 263 डॉलर प्रति मीटरिक टन के मूल्य पर गेहूं आयात करने को यह कह कर खारिज कर दिया कि यह मूल्य अधिक प्रतीत होता है। और केवल 10 दिन के अंदर 325 डॉलर प्रति मीटरिक टन के मूल्य से गेहूं आयात करने का निर्णय ले लिया। इतना ही नहीं इसके भी आगे जाकर 390 डॉलर प्रति मीटरिक टन के मूल्य से 8 लाख टन अतिरिक्त गेहूं के आयात का निर्णय भी कर लिया है। यह पूरी प्रक्रिया किसी घोटाले का संकेत देती है।

भारत के किसानों को समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस कर आत्महत्या तक करने को विवश हो रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार किसानों को केवल लगभग 850 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है जबकि किसानों की मांग 1100 रूपए प्रति क्विंटल की थी। दूसरी तरफ विदेश से लगभग 1600 रूपए प्रति क्विंटल की औसत दर से गेहूं आयात कर रही है। यह सरकार की नीयत और किसानों के प्रति उसकी संवेदनहीनता का प्रमाण है। **हम यह मांग करते हैं कि गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को अपना समुचित हक मिल सके।**

मध्य वर्ग की त्रासदी

भारत में विकास एवं नये आर्थिक अवसरों के चलते विगत 15 वर्षों में मध्यम वर्ग की संख्या और प्रभाव दोनों में बढोतरी हो रही है। उच्च मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो अथवा निम्न मध्यम वर्ग। **यही वह मध्यम वर्ग है, जो नये भारत की तस्वीर के रूप में उभर रहा है।** परन्तु यूपीए सरकार के आने के बाद इस वर्ग को भी नित नयी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक अदद अपना मकान मध्य वर्ग की आवश्यकताओं और सपनों का मुख्य आधार होता है। एनडीए सरकार के शासनकाल में आवास ऋण पर ब्याज की दरें न्यूनतम स्तर पर थी। आज वो डेढ़ गुनी से अधिक हो गयी है। एक अदद मकान फिर सपना होता जा रहा है। नये–नये प्रकार के कर, आधारभूत संरचना की तमाम परियोजनाओं के खटाई में पड़ने से विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नित नये कर मध्य वर्ग पर लगातार बोझ बढ़ा रहे है। जीवन स्तर को उन्नत करने की कीमत लगतार बढ़ रही है। **हम सरकार से यह मांग करते है कि आगामी बजट में सरकार आयकर की सीमा को बढ़ाये और आयकर की दरों को और अधिक व्यवहारिक एवं युक्ति संगत बनाये तथा निम्न आय वर्ग, निर्धन वर्ग एवं कृषि क्षेत्र की जनता के लिए विशेष प्रावधान करें।**

विपक्ष का तिरस्कार

केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लोकतांत्रिक मर्यादा और परंपरा के सर्वथा विपरीत विपक्षी दलों के साथ जिस प्रकार का आचरण किया गया है वह न सिर्फ अनुचित है बल्कि चिंताजनक भी है। विगत तीन वर्षों में गोवा और झारखंड में जिस प्रकार हमारी सरकारों को गिराया गया। झारखंड और बिहार में राज्यपाल के पद का दुरूपयोग करके

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

हमारी सरकारों को बनने से रोकने का प्रयास किया गया। हमारी राज्य सरकारों की मांगों की जैसी उपेक्षा की गई। इतना ही नहीं विदेश नीति जैसे विषय पर जिसमें सभी राजनैतिक दलों में एक आम सहमति होनी चाहिए उस पर हमसे किसी भी प्रकार का विचार विमर्श कभी नहीं किया गया। भारत–अमरीका परमाणु समझौते पर विपक्ष को किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं दी गई। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में तो चुनाव से पूर्व विपक्ष से कोई संवाद करने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि **वर्तमान केन्द्र सरकार का रवैया विपक्ष के प्रति तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक ही नहीं बल्कि अधिनायकवादी प्रवृति का संकेत देता है।** यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण नहीं है। कांग्रेस की यह अधिनायकवादी प्रवृति उसकी फितरत का हिस्सा है। कांग्रेस की परम्परा भी इसी प्रकार की रही है। 1975 का आपातकाल इस मनोवृति की पराकाष्ठा का प्रतीक था।

संसद के अंदर हो अथवा बाहर सरकार ने कभी भी विपक्ष को विश्वास में लेने का प्रयास नहीं किया। इसी कारण संसद की कार्यवाही अनेक बार स्थगित हुई और संसद का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ। भाजपा यह मानती है कि संसद बहस और चर्चा का मंच है इसके समय का समुचित उपयोग होना चाहिए। परन्तु **सरकार के तिरस्कारपूर्ण और अधिनायकवादी रवैये के चलते अनेक बार वे परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो हम नहीं चाहते थे।**

इससे भी अधिक चिंताजनक और हास्यास्पद बात यह है कि सरकार के सहयोगी दल भी संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करके देश का समय नष्ट करते हैं। वामपंथी दल संसद के बाहर सरकार का विरोध करते हैं। संसद के अंदर कार्यवाही बाधित करते हैं परन्तु सरकार को बचाने के लिए संसद में सदैव सरकार के साथ रहते हैं। दोहरे आचरण की यह पराकाष्ठा अब केवल राजनीति में नहीं बल्कि संसद में भी दिखाई पड़ने लगी है। संसद देश की समस्याओं के समाधान का मंच है। परन्तु **यूपीए सरकार और इसके सहयोगी दलों के आचरण एवं विपक्ष के प्रति अवमानना और दमन की मानसिकता के चलते संसद के मंच की गरिमा पर भी आघात पहुंचा है।**

वामपंथी दल बिना किसी उत्तरदायित्व के जिस प्रकार निर्बाध सत्ता संचालन का सुख भोग रहे हैं वह अपने आप में एक विचित्र उदाहरण है। पिछले डेढ़ वर्ष में गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के विधान सभा चुनाव तथा पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नगर–निकाय चुनावों में शायद एक भी सीट वामपंथी दलों को नहीं मिली। फिर भी एक सुपर राष्ट्रीय दल के रूप में हर राष्ट्रीय नीति पर जैसा बलपूर्वक दिशा निर्देश वामपंथी दे रहे हैं उससे लगता है कि **वामपंथी दल मार्क्सवाद की अवधारणा के उलट एक नयी 'एंटी थिसिस' देते हुये, आज की राजनीति के नये ''राजनैतिक बुर्जुआ'' हो गये हैं।** जो देश की सर्वहारा के भविष्य को अपनी स्वेच्छाचारिता से अनिश्चित करके आत्ममुग्ध हो रहे हैं।

परमाणु समझौता एवं भारत अमेरिका संबंध

हाल ही में हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर भाजपा का मत पहले से ही स्पष्ट है। इस समझौते की दिशा में समय–समय पर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

हम अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करते रहे है। परन्तु पिछले दिनों वामपंथी दलों ने इस विषय को जिस रूप में उठाया वह राष्ट्रीय हितों से कम और पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिक प्रतीत होता है। इस समझौते पर हमारा विरोध न केवल विरोध के लिए था और न ही वामपंथी दलों की तरह अंध अमेरिका विरोध के लिए था। **हमारा विरोध देश की सम्प्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए था। हमारा विरोध रणनीतिक स्वतंत्रता को रणनीतिक अनुचरता (पिछलग्गूपन) में बदलने से रोकने के लिए था।**

भाजपा पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर न किसी देश के विरोध में है न समर्थन में। जहां तक अमेरिका का संबंध है **भारत अमेरिकी संबंधों का सबसे शानदार समय वाजपेयी सरकार का समय था।** हमने भारत अमेरिका संबंधों में युगान्तर स्थापित किया। पहले 1998 में पोखरण विस्फोट करके अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष किया। 1999 में आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सीएटल की विश्व व्यापार संगठन बैठक में भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित होने दिये। यानि अपने सामरिक और आर्थिक दोनों हितों की रक्षा करते हुए स्वाभिमान के साथ बराबरी के स्तर पर अमेरिका के साथ दोस्ती का नया अध्याय प्रारंभ किया। **अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों का सबसे शानदार अध्याय भी एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। हम इसे आगे भी जारी रखना चाहते है।**

कांग्रेस हो अथवा वामपंथी दल इन सभी ने 1998 में पोखरण विस्फोट का विरोध किया था। वामपंथियों ने इसे अनावश्यक तक कहा था। वामपंथी 1964 में चीन के परमाणु विस्फोट का समर्थन करते थे परन्तु 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट का विरोध करते थे। परन्तु आज वे परमाणु विस्फोट की स्वतंत्रता के समर्थक हो रहे है। **अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस और वामपंथी दोनों को भारत की आणविक क्षमता से कोई सरोकार न पहले था और न अब है। वे परमाणु मुद्दे पर केवल राजनीति की रोटी सेंक रहे है।**

भारत सरकार ने परमाणु समझौते पर भारत के दीर्घकालिक सामरिक हितों के साथ समझौता करने की गलती की है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आणविक सम्प्रभुता पर नियंत्रण और विदेश नीति पर दबाव स्वीकार नहीं कर सकते। **अतः हमारा यह मानना है कि भारत–अमेरिका परमाणु समझौते को अंतिम रूप में स्वीकार करते हुए लागू करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।** भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनारावृति न हो इसके लिए यह व्यवस्था की जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन संसद की पुष्टि के बाद ही हो सकता है। क्योंकि संसद देश के जनमानस की सामूहिक अभिव्यक्ति और आकांक्षा को परिलक्षित करती है। किसी भी संधि पर संसद का अनुमोदन यह सुनिश्चित करेगा कि कभी भी सत्ताधारी दल अथवा दलों की पूर्वाग्रह की छाया राष्ट्रीय हितों पर न पड़ सकें।

पड़ोसी देश

यूपीए सरकार के केन्द्र में आने के बाद भारत की विदेश नीति की असफलता जगजाहिर है। हमारे पड़ोसी देशों के प्रति भारत सरकार की नीति पूरी तरह भ्रामक एवं निष्प्रभावी है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

हवाना में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। **इस एक वक्तव्य के द्वारा प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद के विरूद्ध हमारे वर्षों के रणनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक दबाव को एकाएक समाप्त कर दिया।** हाल ही में जनरल मुर्शरफ ने पाकिस्तान के एक साप्ताहिक टीवी कार्यक्रम में यह कहा कि हमने पुराने मुद्दों को नहीं छोड़ा है, और भारत सरकार को भी इस बात के लिए राजी कर लिया है कि जम्मू कश्मीर मुख्य मुद्दा है। जनरल मुर्शरफ ने इसे भारत की विदेश नीति में ''सी चेंज'' की संज्ञा दी है। पता नहीं यह ''सी चेंज'' भारत के हितों को अनिश्चय के किसी सागर में धकेल देगा।

एनडीए सरकार के शासनकाल में इन्हीं जनरल मुर्शरफ ने न सिर्फ अपनी धरती से भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियां संचालित न होने देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी बल्कि यह भी कहा था कि कश्मीर से अलग हटकर अन्य मुद्दों पर भी बात की जा सकती है। **आज पाकिस्तान का यह बदलता रूख एनडीए सरकार की तुलना में वर्तमान यूपीए सरकार की घोर कूटनीतिक विफलता का प्रमाण है।**

देश की जनता को यह समझ में ही नहीं आता है कि श्रीलंका की आंतरिक परिस्थितियों में भारत किस ओर खड़ा है। नेपाल के प्रति भारत सरकार की पूरी नीति वामपंथी दलों के इशारों पर उस दिशा में बढ़ गयी जो भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिए भी चिन्ता का विषय बन गयी। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक संघर्ष के साथ–साथ अब बंगलादेश में भी ऐसी ही आंतरिक संघर्ष की स्थितियों बन रही है। बंगलादेश भारत के विरुद्ध गतिविधियों का नया केन्द्र बनकर उभर रहा है। उल्फा उग्रवादी बांग्लादेश में शरण लिये हुये हैं। वे वहां से आतंकी प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं और असम में जब तब खूनी हिंसा करते रहते हैं। बांग्ला देश में आई.एस.आई. ने अपनी गतिविधियां और शिंकजा अधिक मजबूत कर लिया है। इतना सब कुछ होने पर भी भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से कोई आपत्ति तक नहीं दर्ज कराई है जिससे कम से कम इतना संदेश तो जा सके कि भारत बांग्लादेश की इन गतिविधियों से खुश नहीं है।

यूपीए सरकार की शुतुरमुर्गी दृष्टि शायद यह सब देख ही नहीं पा रही है। चीन और पाकिस्तान तो अपना रणनीतिक सहयोग इस सीमा तक बढ़ा रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान में ग्वादार में डीप नैवल बेस तैयार किया है। अब तो यह तथ्य भी प्रकाश में आ गया है कि हाल के वर्षों में चीन ने भारी मात्रा में हथियार बंगलादेश को मुहैया कराये। ऐसी जानकारियां भी आई हैं कि चीन ने बर्मा और श्रीलंका के कुछ द्वीप समूहों पर जासूसी के लिए मॉनिटरिंग यंत्र लगाये हैं ताकि भारतीय नौ–सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। भारत की लचर विदेश नीति के चलते ही चीन का हौसला इतना बढ़ा कि उसने अरूणाचल पर एक बार फिर अपना दावा पेश कर दिया है। श्रीलंका की आतंरिक स्थितियों में पाकिस्तान के सहयोग की बातें भी कहीं जा रही है। नेपाल के माओवादियों और पाकिस्तान की आई.एस.आई. के गठजोड़ की खबरें लगातार आती रहती हैं। तालिबान फिर अफगानिस्तान में मजबूत हो रहा है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

यानि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत के चारों तरफ पड़ोसी राष्ट्रों में हो रही गतिविधियों के बीच इस सरकार के रहते भारत के सामरिक एवं रणनीतिक हित कैसे सुरक्षित रहेंगे इसकी कोई संभावना नहीं दिखती।

रामसेतु

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय छवि हो अथवा भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, यूपीए के शासनकाल में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। **केन्द्र में यूपीए वामपंथी गठजोड़ की सरकार आने के बाद से ही हिन्दू समाज के मान बिन्दुओं पर निरंतर कुठाराघात किया जाता रहा है।** पिछले दिनों तो इसकी पराकाष्ठा को गयी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में रामसेतु के संदर्भ में दायर हलफनामें में यह कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम सहित रामायण के सभी पात्र कभी रहे ही नहीं इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। भाजपा के प्रबल विरोध के चलते सरकार ने हलफनामा वापिस लेकर तीन महीनें का समय मांगा है। **परन्तु सरकार की हिन्दू विरोधी मानसिकता का प्रमाण इस हलफनामें से मिल चुका है।**

जहां तक वैज्ञानिकता और ऐतिहासिकता का प्रश्न है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस सरकार ने क्या भारत में रामायण से जुड़े सभी स्थानों की ऐतिहासिकता प्रामाणिक करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रयास किया ? यदि नहीं तो किस प्रामाणिकता के आधार पर इतना बड़ा वक्तव्य दे दिया। वैसे जनआस्था से जुड़े विषयों को ऐतिहासिकता और वैज्ञानिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। अन्यथा इससे तमाम मत सम्प्रदायों के मान बिन्दुओं पर आक्षेप करने का एक ऐसा दौर शुरू हो सकता है जो नये गंभीर साम्प्रदायिक टकराव को जन्म दे सकता है।

हमारा स्पष्ट मानना है कि भगवान राम भारत के कण–कण में, जन–जन में, हर मन में शाश्वत रूप में स्थापित ही नहीं है बल्कि सतत् जनमानस को अनुप्रामाणित करते रहते है। यदि राम थे ही नहीं तो मैं केन्द्र की सत्ता में बैठकी कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहूंगा कि फिर महात्मा गांधी के रामराज्य का स्वप्न क्या खोखले आधार पर टिका हुआ छलावा था ? **भगवान राम की अवमानना करके कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के निम्नतम स्तर का परिचय दिया है। जनआस्थाओं के साथ राजनैतिक खिलवाड़ का एक ऐसा अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए।**

क्षमा मांगने की बात मैं किसी राजनैतिक आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति अपने समर्पण के आधार पर कह रहा हूं, कि **राम के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत तो गुलामी के काल में किसी प्रत्यक्ष विदेशी शासन ने भी नहीं की। फिर यह सब इस कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन से कारण हैं, इसे कौन सी शक्ति संचालित कर रही है, और ये शक्ति भारत के मूल स्वरूप को क्यों विकृत करना चाहती है? देश की जनता को इन प्रश्नों का उत्तर चाहिये।**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

रामसेतु केवल पत्थर और चट्टानों से बना कोई ढांचा नहीं है जिसके मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक होने पर बहस की जाये बल्कि राम सेतु भारत के शाश्वत आदर्शों का सेतु है, आसुरी वृत्तियों का दमन करके धर्म की स्थापना के मार्ग का सेतु है। केवल धार्मिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से ही बल्कि वैज्ञानिक, सामरिक, सुनामी से सुरक्षा और परमाणु उर्जा पूर्ति की क्षमता आदि किसी भी दृष्टि से राम सेतु का विध्वंस भारत के लिए घातक होगा। भाजपा हर स्तर पर इसका विरोध करेगी।

अल्पमत की सरकार

अपनी असफल और असंवेदनशील नीतियों के चलते सरकार जनता के विश्वास को तो पहले ही खो चुकी थी। अब द्रमुक जैसे सरकार के अंदर के सहयोगी दल, कम्युनिस्ट पार्टियों सरीखे समर्थक दल, सभी सरकार के विरोध की भाषा बोल रहे हैं। सरकार भारत और भारतीयता के प्रतीकों के विरोध की भाषा बोल रही है। यानी **यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, गठबंधन के सहयोगी दलों का विश्वास खो चुकी है, गठबंधन के बाहर के दलों का विश्वास खो चुकी है। अतः इस सरकार को आज के दिन संसद का विश्वास प्राप्त है यह नहीं माना जा सकता। मैं यह मानता हूं कि सरकार संसद में व्यावहारिक रूप से अल्पमत में आ चुकी है।** इसी भय के चलते संसद का सत्रावसान कर दिया गया। मैं देश की जनता की ओर से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन परिस्थितियों में अपनी विश्वासनीयता प्रमाणित करने के लिए वह तत्काल संसद का सत्र बुलाये और विश्वास मत हासिल करे।

यदि सरकार में संसद का सामना करने का साहस नहीं बचा है तो उसे सत्ता छोड़ कर जनता के बीच में आये। भाजपा इसके लिए तैयार है और सरकार को जनता के बीच आने की चुनौती देती है।

विकास की पर्याय भाजपा

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि केन्द्र में एनडीए सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल में विकास के जिस मॉडल को प्रारंभ किया गया आज वही भारत का एक नया ढांचा बना रहा है। परन्तु दुःख का विषय है कि हमने ढांचागत संरचना के लिए जो व्यापक योजनाएं बनाई थीं उनमें से कई की तो गति बहुत धीमी है तो कई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आदरणीय अटल जी के 'ड्रीम प्रोजेक्ट' कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की मूल योजना के अनुसार अब तक इसका कार्य लगभग संपन्न हो जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं हो सका। ऐसा मैं विश्वासपूर्वक इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इस परियोजना के प्रारंभ के समय संयोग से मैं स्वयं जल–भूतल परिवहन मंत्री था। प्रधानमंत्री मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गति भी असंतोषजनक रही। कृषि आमदनी बीमा योजना को लागू होने से पहले ही रोक दिया गया। 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के समकक्ष चिकित्सा संस्थान खोलने की परियोजना पर इस सरकार ने चर्चा तक नहीं की। देश में सिचाई की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए शुरू की गई अनेक परियोजनाओं और एनडीए सरकार द्वारा परिकल्पित नदी जोड़ो परियोजना पर तो इस सरकार ने विचार करना भी उचित नहीं समझा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

आज भी जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं उनमें विकास के अनेक उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। केन्द्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना को हम उपयुक्त नहीं मानते परन्तु इसके क्रियान्वयन में भी भाजपा शासित राज्यों का अग्रणी स्थान है। कानून व्यवस्था और जेहादी आतंकवाद की घटनाओं पर भी हमारी सरकारों ने प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सफलता पाई है। मध्य प्रदेश को जिस दुर्दशा की स्थिति में भाजपा ने पाया था आज उससे बहुत बेहतर स्थिति तक पहुंचाने में सफलता पाई है।

आगामी चुनौतियां

आने वाले महीनों में बहुत शीघ्र ही गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। गुजरात राज्य की सरकार ने इसे विकास के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। गुजरात की विकास दर देश की विकास दर से डेढ़ से पौने दोगुनी है। बिना किसी विवाद के विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण और सर्वाधिक विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने में गुजरात सरकार की भूमिका प्रशंसनीय है। विगत 12 वर्षों से वहां भाजपा की सरकार है। श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड बनाया है। गुजरात सरकार की प्रशंसा पूर्व राष्ट्रपति डा0 अब्बुल कलाम और राजीव गांधी फाउंडेशन तक ने भी की है। परन्तु चुनाव के समय निश्चित रूप से संगठन के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर पार्टी की विजय का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। **मुझे विश्वास है कि सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर गुजरात के इस चुनावी समर में भाजपा को विजयश्री दिलाएगें।**

अगले वर्ष होने वाले कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनावों नजदीक आते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो नजदीक आते दिख ही रहे हैं। हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि केन्द्र सरकार के विरूद्ध स्थापना विरोधी लहर का का हमें स्वतः ही लाभ मिलेगा। इस लाभ को प्रभावी रूप से अपने पक्ष में प्रयोग करने के लिए पार्टी संगठन और सांसदों को कटिबद्ध होकर अपने–अपने चुनावी क्षेत्रों में अभी से सक्रिय हो जाना चाहिए। सामान्यतः लोकसभा चुनावों में हमारे काफी सांसद पुनः चुनकर नहीं आ पाते। यदि हम इस परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकें तो अगली लोकसभा में हमारी संख्या बहुत प्रभावी हो सकती है।

कसौटी का समय

देश में वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियां विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार से चल रही हैं वह दर्शाता है कि भविष्य में हमें राजनैतिक और सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर बना हुआ संशय का वातावरण समाप्त हो चुका है। कर्नाटक में हमारे संगठन और गठबन्धन दोनों की सुदृढ़ता बनी रहेगी ऐसी मेरी आशा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुनः पुरानी स्थिति में पहुंचने का प्रयास हमें करना होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ में अपनी यथास्थिति को बनाये रखने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव नजदीक हैं। यहां हमारी गठबंधन सरकार भी है। मुझे आशा है कि हम नागालैंड के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

इसके अतिरिक्त अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में हमारे लिए कई संभावनायें हो सकती हैं।

पिछली बार मैंने सरकार पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर समुचित ध्यान न देने का आरोप लगाया था। **हमने यह मांग की थी कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट भौगेलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रख कर पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान करे। मैं एक बार फिर भाजपा की इसी मांग को पूरा किये जाने का आग्रह केन्द्र सरकार से करता हूं।**

2004 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद सिर्फ हमें राजनैतिक दृष्टि से ही असफलता का सामना नहीं करना पड़ा बल्कि मीडिया ने हमारी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिह्न लगाया। एनडीए के कुछ दलों से हमारे संबंधों में भी पहले जैसी मधुरता का अभाव दिखा। यदि इसे संक्षिप्त रूप में कहना हो तो हमारे विरोधियों ने एक ऐसा वातावरण बनाया कि भाजपा के संगठन की क्षमता, गठबंधन की एकजुटता और विचारधारा की प्रतिबद्धता तीनों के विषय में भ्रम उत्पन्न किया जा सके। हमें भ्रम का यह वातावरण समाप्त करना है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव जब कभी भी होंगे तो हमें एक नहीं बल्कि इन तीनों विषयों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

भाजपा हर बूथ पर

संगठन की शक्ति सदैव से हमारी विशेषता रही है। इसी शक्ति को विस्तार देने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे संगठन का विस्तार हर बूथ तक होना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी प्रदेशों का संगठन इस अभियान में पूरी शक्ति के साथ लगा होगा। मैं समय–समय पर इन बूथ कमेटी के सदस्यों से स्वयं भी सीधे दूरभाष पर बात करने का प्रयास करता रहूंगा। अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट जिले की एक बूथ कमेटी के सदस्य से सीधे मैंने बात की। हमें **समाज से इस स्तर तक का संबंध स्थापित करना होगा। इसी में हमारे संगठन की शक्ति, सामाजिक संतुलन की कुंजी और दीनदयाल जी के अंत्योदय के स्वप्न का यथार्थ छुपा है।**

संकल्प

अन्त में मैं आपको भोपाल में हुई अपनी पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्मरण दिलाना चाहता हूं पिछली बार भोपाल में 11 वर्ष पूर्व सन् 1996 में 21,22 एवं 23 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी पंडित दीनदयाल परिसर में हुई थी। संयोग से आज जब हम यहां माह सितम्बर सन् 2007 में बैठे हैं तो तिथियां वहीं है। भोपाल में सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक ऐतिहासिक थी। उस बैठक में हमारे नेता मा0 अटल जी प्रधानमंत्री पद पर तेरह दिन रहते हुए त्यागपत्र देकर लौटे थे। देश की राजनैतिक परिस्थितियां नया स्वरूप ले रहीं थी। हम संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। अपने लोकप्रिय

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

नायक अटल जी के त्यागपत्र से देश दुखी था, वहीं वामपंथियों और कांग्रेस की चालों से देश पूरी तरह त्रस्त था। सन् 1996 में सभी तथाकथित सेक्युलर दल भाजपा रोकने में लगे थे, पर हम सन् 1998 में और बढ़े। फिर 1999 में बढ़े। अटल जी ने छह वर्ष तक प्रधानमंत्री रहकर विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। अन्य 24 दलों को साथ लेकर गठबंधन की राजनीति का इतिहास रचा।

आज भी वैसे ही हालात दिख रहे हैं। भूमिकाएं जरूर थोड़ी बदली है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को वामपंथी बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सन् 1996 में अंतर इतना ही था कि वामपंथी सत्ता में थे और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। उस समय भी संयुक्त मोर्चा सरकार अल्पमत में थी। आज भी यूपीए सरकार अल्पमत में है। उस समय भी मध्यावधि चुनाव हुए, आज भी आसार बन रहे हैं। उस समय भी देश में अनिश्चित्ता, अराजकता एवं अस्थिरता का भीषण और भयावह दौर था। फिर भी सत्ता धारी दल के सहयोगी दलों में एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेला जा रहा था। आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम यहां विचार करेंगे। वहीं स्थान है, वहीं परिस्थितियां है, वहीं दल है आवश्यकता है केवल उसी आत्मविश्वास और उसी प्रतिबद्धता को प्रखर रूप में सामने लाने की। **मुझे विश्वास है कि भोपाल की पिछली कार्यकारिणी की तरह एक बार फिर हम यहां से नये इतिहास का श्रीगणेश करेंगे। और जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए महान भारत बनाने के अधूरे स्वप्न को निर्णायक परिणिति तक पहुंचायेंगे।**

वन्दे मातरम् !

****

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com